जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 52 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 25 दिसम्बर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

'पनामा कैनाल अमेरिका द्वारा अमेरिकी पैसे से बनाई गयी'

ट्रम्प ने इस तर्क के साथ, पनामा कैनाल का संचालन व नियंत्रण हथियाने का इरादा जताया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। अब तक उपलब्ध प्रारंभिक संकेतों से स्पष्ट है कि नया साल -2025- सभी देशों के लिए परेशानी भरा होने वाला है। भारत को आने वाले असमंजस भरे साल को समझदारी से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठाना चाहिए।

डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नई कार्य व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पनामा नहर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की बात कही है। इसके साथ-साथ, कैनडा को अमेरिका का 51 वां राज्य बनाने की बात कहने के बाद, अब ट्रंप ने समुद्र के पार ग्रीनलैंड खरीदने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि विश्व शांति तथा फ्री वर्ल्ड के सरवाइवल के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए।

दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की, अन्य देशों पर कब्जा करने की नीति, अन्य देशों की इस प्रवृत्ति को लगभग वैध बना देती है। इसे नए अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे अच्छा तोहफा मानकर, व्लादिमिर पुतिन ने, यूक्रेन के क्षेत्रों को छीनकर रुस का हिस्सा बनाने के अपने कदम के लिए यूरोप में समर्थन जुटाने के प्रयास शुरु कर दिए हैं।

- जैसा कि विदित ही है, अमेरिका ने पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, एक राजनीतिक आंदोलन को फण्ड करके व पनामा व कोलंबिया का विभाजन करवाया था तथा एक नये देश पनामा का जन्म हुआ था।
- पनामा के स्वतंत्र होने के बाद, अमेरिका ने कैनाल का निर्माण किया था तथा काफी अर्से तक कैनाल पर अमेरिका का कंट्रोल था।
- 1964 में पनामा में आंदोलन व अशांति के बाद कैनाल का कंट्रोल पनामा को सौंप दिया गया था।
- अब ट्रम्प अमेरिका के व्यापार व ट्रेड के हित में कैनाल का नियंत्रण पुनः अपने हाथ में लेना चाहता है, क्योंकि ट्रम्प के अनुसार, पनामा बहुत भारी दाम वसूल कर रहा है कैनाल के उपयोग के लिये और यह अमेरिका के ट्रेडिंग व व्यापार के हित में नहीं है।
- ट्रम्प की ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' (अमेरिका को पुनः महान बनाओ) नीति के अंतर्गत अमेरिका ग्रीनलैंड का भी अधिग्रहण करने की मंशा रखता है। जैसे अलास्का को रूस ने उन्नीसवीं शताब्दी में खरीदा था, उसी तरह अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है।
- ट्रम्प के विस्तारवादी इरादों से प्रेरित होकर रूस ने भी यूरोप के छोटे-मोटे देशों पर कब्ज़ा करने का इरादा अपनाया है।

पुतिन ने सार्वजनिक गलत सूचना अभियान के साथ-साथ, यूरोप की कुछ सरकारों को अस्थिर करने के भी प्रयास शुरु कर दिए हैं। पुतिन के सहायक कह चुके हैं कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसे समर्थन देने को लेकर यूरोप के देशों में भारी मतभेद हैं।

ट्रम्प के तथाकथित ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' प्लान में, पनामा कैनाल पर कब्जा करना सबसे भयावह व गंभीर है। ट्रम्प ने कहा है कि यह नहर, जो पहले अमेरिका के नियंत्रण में थी, अमेरिका के व्यापारिक व आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे फिर अमेरिका के नियंत्रण में लाना चाहिए।

पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुलिनो ने कहा है कि नहर का प्रत्येक मीटर पनामा का है और नहर और आस-पास की भूमि पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रम्प इससे हतोत्साहित नहीं हैं और उन्होंने युवा अमेरिकी कंज़र्वेटिव्स के एक समूह से कहा है कि राष्ट्रपति कार्टर द्वारा पनामा सरकार को नहर पर नियंत्रण देने का कदम एक गलती थी।

डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा के लोगों के खिलाफ अभियान जारी रखा है। उनका कहना है कि पनामा नहर का उपयोग करने के लिए पनामा अमेरिका से बहुत अधिक शुल्क ले रहा है। ट्रम्प का दावा है कि पनामा नहर को अमेरिकी धन से बनाया गया था।

दोनों देशों के बीच उलझे हुए रिश्तों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव नियमों में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट पहुँची कांग्रेस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा वैबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग्स जैसे इलैक्ट्रॉनिक डॉक्युमैंट्स का सार्वजनिक निरीक्षण रोकने के लिए सरकार ने गत शुक्रवार को चुनाव नियमों में बदलाव किया था। एक अधिसूचना द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज़ अब जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने

- केन्द्र सरकार ने सी.सी.टी.वी. और वैबकॉस्टिंग फुटेज की जाँच पर रोक लगाने के लिए गत शुक्रवार को चुनाव नियमों में बदलाव कर दिया था।

पोल पैनल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एकतरफा निर्णय लेकर ''जल्दबाजी'' में संशोधन किया है। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट ''नष्ट हो रही'' चुनाव प्रक्रिया को बहाल करेगा। कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पार्टी ने ''कन्डक्ट ऑफ इलैक्शन रुल्स, 1961'', में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है तथा पुरजोर ढंग से कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग, जिस पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है, ऐसे महत्वपूर्ण कानून में बदलाव करने का जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता।

जे.पी. नड्डा के आवास पर आज होगी एन.डी.ए. की मीटिंग

शाह की टिप्पणी के मुद्दे पर उग्र विपक्ष के खिलाफ जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच, एन.डी.ए. के सभी पार्टनर बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के निवास पर इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे तथा विवाद की काट करने की रणनीति पर विचार करेंगे।

इस समय, भाजपा के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। भाजपा को कुछ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मुद्दों पर एन.डी.ए. पार्टनर्स के साथ मित्रता के माहौल में एक एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है। इन मुद्दों में शामिल हैं- ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' विधेयक तथा ''वक्फ संशोधन'' विधेयक। ये दोनों ही विधेयक विस्तृत संवीक्षा के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे हुये हैं।

प्रधानमंत्री के रुप में नरेन्द्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में लोकसभा की संरचना बदली हुई है। इस वजह से भाजपा नेतृत्व छोटे-बड़े सभी मुद्दों पर अपने सभी मित्र दलों को साथ लेकर चलने की जरुरत के विषय में बहुत सावधानी से काम लेता प्रतीत हो रहा है। भाजपा ज्यादा सचेत खासतौर से इसलिये भी है क्योंकि विपक्षी नेता अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी के सम्बंध में भाजपा और एन.डी.ए. पार्टनरों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

- प्र.मंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लोकसभा में समीकरण बदल गए हैं। अब घटक दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। यही कारण है कि भाजपा एन.डी.ए. की बैठक बुला रही है, ताकि घटक दलों को छिटकने से रोका जा सके।
- भाजपा को ''एक राष्ट्र एक चुनाव बिल'' और वक्फ संशोधन बिल पर सहयोगी दलों की सख्त जरूरत है।
- इसके अलावा भाजपा को आशंका है कि शाह की अंबेडकर संबंधी टिप्पणी पर कहीं सहयोगी दल विपक्षी दलों की बातों में न आ जाएं।

पूर्व प्रधानमंत्री तथा भाजपा के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वीं वर्षगाँठ वाले दिन हो रही इस मीटिंग में, भाजपा गठबन्धन पार्टनरों के सम्मुख एक समझौता प्रस्ताव रखने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी संभावना है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिये, भाजपा अपने गठबन्धन पार्टनरों - जनता दल यूनाइटेड (जे.डी.यू.) तथा चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को कुछ सीटों की पेशकश करेगी। भाजपा के लिये बिहार की इन दोनों पार्टियों को प्रसन्न रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के विधानसभा अगले वर्ष ही होने हैं।

जहाँ प्रधानमंत्री के रुप में मोदी के प्रथम दो कार्यकालों में एन.डी.ए. की मीटिंग बहुत की कम हुई थीं, वहीं, भाजपा नेतृत्व इस बार, तर्कसंगत कारणों से, इस प्रकार की मीटिंगें करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। अभी -अभी समाप्त हुये संसद के शीतकालीन सत्र में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एन.डी.ए. पार्टनरों से कहा था कि बेहतर समन्वय बनाये रखने के लिये हर महीने मीटिंग हुआ करेगी।

इस वर्ष हुये लोकसभा चुनावों में, अपने बलबूते पर लोकसभा में बहुमत लाने में भाजपा की असफलता मानसिक रुप से पार्टी को सहज नहीं होने दे रही, जबकि अभी हाल ही में, उसने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते हैं। विपक्ष, लोकसभा में अच्छे संख्याबल के चलते, भाजपा के सामने चुनौतियाँ खड़ी करता आ रहा है। अगर आगामी महीनों और वर्षों में कुछ राज्यों में भाजपा को हार का मुँह देखना पड़ा, तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी।

बेलगांव में 26 दिसम्बर 1924 को महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया, सभी जिलों में कांग्रेस सप्ताह भर आंदोलन करेगी, फिर राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन देकर शाह के इस्तीफे की मांग करेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। बेलागावी (अब बेलगाँव) में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के चुनाव का स्मरणोत्सव मनाने के उद्देश्य से, कांग्रेस बेलगाँव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की विस्तृत मीटिंग आयोजित कर रही है। इस ऐतिहासिक मीटिंग में करीब 200 पार्टी-नेता शामिल होंगे।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि 26 दिसम्बर को अपरान्ह 2:30 बजे बेलगाँव के महात्मा गांधी नगर में ''नव सत्याग्रह बैठक'' होगी। इससे एक दिन बाद 27 दिसम्बर को वहाँ ''जय बापू, जय भीम, जय संविधान'' सभा होगी, जिसमें लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि वस्तुतः यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जब पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने महान नेता महात्मा गांधी की अध्यक्षता के 100वें वर्ष का सुखद स्मरणोत्सव मनायेगी।

- बेलगांव में कांग्रेस कार्य समिति की नव सत्याग्रह बैठक हो रही है। इसके अगले दिन ''जय बापू, जय भीम, जय संविधान'' रैली होगी।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बेलगांव का कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक महत्व है। सौ साल पहले 26 दिसम्बर 1924 को यहीं महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और सेवा दल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पूर्व बेलगांव से ही सत्याग्रह की घोषणा की थी और 100 वर्ष बाद, उसी दिन कांग्रेस 'नव सत्याग्रह'' का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस सांसद और पार्टी कार्यकर्ता 27 दिसम्बर को वहाँ उपस्थित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह मीटिंग, ढाई साल पहले उदयपुर में हुये चिन्तन शिविर की तरह, एक ऐतिहासिक मीटिंग का रूप लेने जा रही है। ज्ञातव्य है कि ''भारत जोड़ो यात्रा'' का विचार उसी चिन्तन शिविर की देन था।

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। भारत के राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं। डॉ हरि बाबू कंभमपति, जो मिज़ोरम के राज्यपाल थे, अब ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

पूर्व सेना प्रमुख, जनरल वीके सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल होंगे।

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र

- पांच राज्यों के राज्यपाल बदले।

विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल होंगे। इसके अलावा, अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों के साथ, संबंधित राज्यों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आएगा और राज्यपाल नए पदभार संभालेंगे।

भारत अमेरिका के उद्योगपतियों को भारी रियायतें देने की तैयारी में है

भारत अमेरिका से आयातित ''पोर्क'' (सूअर का मांस) मेडिकल उपकरण, लग्ज़री मोटर साइकिल आदि, पर, वर्तमान में लगी भारी कस्टम ड्यूटी को घटायेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प जब पद ग्रहण करेंगे, उस समय भारत अमेरिकन निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। कुछ खास प्रकार के अमेरिकी सामानों पर शुल्क घटाने की भी योजना है, जैसे पोर्क, चिकित्सकीय उपकरण और लग्ज़री मोटर साईकिल आदि। इसका उद्देश्य संभावित प्रतिस्पर्धी करों को संबोधित करना और व्यापक व्यापार और निवेश समझौते की राह आसान करना।

ग्लोबल ट्रेड गतिशीलता के संभावित बदलाव को पहचान कर खासकर चीन के आयात पर ट्रम्प द्वारा 60 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा करने को ध्यान में रखते हुए भारत का उद्देश्य खुद को निर्माण निवेशों के लिए अनुकूल विकल्प के रूप में स्थापित करना है।

- जैसा कि विदित ही है, ट्रम्प का चीन से अमेरिका में आयात होने वाले माल पर 60 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाने का इरादा है। इससे चीन का माल महंगा हो जायेगा अमेरिका में।
- भारत, चीन के इस महंगे माल की तुलना में अपने उपकरण व उत्पाद आदि को अमेरिकी औद्योगिक श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहता है।
- अमेरिका को लुभाने के लिये भारत, अमेरिका से भारत में आयातित होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी कम कर देना चाहता है।
- अगर, भारत का अमेरिका से आयात बढ़ेगा, तो स्वतः ही व्यापारिक संतुलन बनाये रखने के लिये, अमेरिका भी भारत से आयात बढ़ायेगा और, अमेरिका की औद्योगिक श्रृंखला में भारत में उत्पन्न सामान को हिस्सा मिल जायेगा।

अमेरिकन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत विमानों के रख रखाव, सेमी कंडक्टर्स और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है। जो कंपनियां अपने निर्माण को नए आयामों पर ले जाना चाहती हैं, उनके लिए भारत को आकर्षक विकल्प बनाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है और अर्थव्यवस्था को ज्यादा उदार बनाकर अमेरिकन निवेश को आकर्षक बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत दे रही है।

व्यापारिक असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत अमेरिका से हर साल 5 से 10 अरब डॉलर की लिक्विफाइड नैचुरल गैस और रक्षा उपकरणों का आयात करने पर विचार कर रही है। इससे द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और भारत की इस इच्छा का भी संकेत मिलता है कि वह प्रतिस्पर्धी व्यापार में दिलचस्पी रखता है।

भारत का लक्ष्य अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला से गहरा जुड़ाव रखना और दोनों देशों के बीच परस्पर आर्थिक निर्भरता को बढ़ाना है। ये प्रोत्साहन देना भारत उन अमेरिकी निर्माताओं को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार

जयपुर, 24 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विवाहिता बेटी को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति का हकदार मानने वाले एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर राज्य सरकार

- हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को कायम रखते हुए इसके खिलाफ दायर सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमने तो जस्टिस रोहिन्टन एफ. नरीमन और जस्टिस के. मैथ्यु जोसफ के नाम दिए थे'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर विरोध जताते हुए राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर विचार तक नहीं किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी ने ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'' के सदस्यों और अध्यक्ष के चयन पर अपना विरोध दर्ज करा दिया था।

उन्होंने आयोग के अध्यक्ष पद के लिये जस्टिस रोहिन्टन फली नरीमन तथा जस्टिस कुट्टियिल मैथ्यू जोसफ के नाम प्रस्तावित किये थे। लेकिन विपक्ष के सुझाव की उपेक्षा करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने एन.एच.आर.सी. के नये अध्यक्ष पद के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी. रामासुब्रमन्यम को नियुक्त कर दिया है।

एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिये चयन समिति की मीटिंग 18 दिसम्बर को संसद भवन में हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस हाई पावर कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल थे- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।

खड़गे और राहुल का आरोप है कि विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने तथा सामूहिक निर्णय सुनिश्चित करने के बजाय, कमेटी ने नाम को अंतिम रूप देने के लिये संख्यात्मक बहुमत पर भरोसा किया तथा मीटिंग के दौरान उठाये गये वाजिब सरोकारों तथा परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान ही नहीं दिया।

- राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो चयन समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय कर रखा था किसे अध्यक्ष बनाना है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति के सदस्य हैं, गृह मंत्री शाह, लोकसभा स्पीकर बिड़ला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे।
- केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है।

असहमति की टिप्पणी में कहा गया कि मैरिट निश्चित रूप से प्राथमिक शर्त होती है, लेकिन राष्ट्र की क्षेत्रीय, जातीय, समुदया संबंधी तथा धार्मिक विविधता को दर्शाने वाला संतुलन बनाये रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

अठारह दिसम्बर को दिये गये विरोध सूचना टिप्पणी (डिसेन्ट नोट) में कहा गया, ''अंत में, आज की मीटिंग में चयन समिति द्वारा अपनाया गया विचार-विमर्श पर ध्यान नहीं देने का तौर-तरीका अत्यधिक दुखद है। एन.एस.आर.सी. की विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता, विविधतापूर्ण एवं समावेशी होने, जो भारत के संविधान की प्रकृति को परिभाषित करते हैं, की सामर्थ्य पर निर्भर होती है।''

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज रामासुब्रमण्यम को एन.एच.आर.सी. का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

प्रियांक कानूनगो तथा डॉ. जस्टिस बिद्युत रंजन सारंगी (रिटायर्ड) एन.एच.आर.सी. के सदस्य नियुक्त किये गये।

कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत

करौली, 24 दिसम्बर (निस)। गंगापुर सड़क मार्ग पर सलेमपुर गांव के पास स्विफ्ट डिज़ायर कार और बस में आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 5 महिला -पुरुषों की मृत्यु हो गई।बस में सवार करीब डेढ़ दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, करौली की ओर से कार गंगापुर की तरफ जा रही थी। प्राइवेट बस गंगापुर से करौली की तरफ आ रही थी। गंगापुर और सलेमपुर के बीच स्थित छात्रावास के पास दोनों वाहन आमने-सामने से टकरा गए। हादसे में कार चालक सहित

- गंगापुर रोड पर सलेमपुर गाँव के पास हुए इसे हादसे में कार में सवार 5 महिला-पुरुषों की मौत हो गई, डेढ़ दर्जन बस यात्री घायल हो गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)